कर रही है । इसके अतिरिक्त, राज्य स्तर के समन्वयक और राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग भी राज्य में एल.पी.जी. की उपलब्धता की समय समय पर समीक्षा करते हैं । इन क्षेत्रों में आपूर्ति करने वाले विभिन्न बाजारों और डिस्ट्रीब्यूटरशिपों से संबंधित सूचना भी एकत्र की जाती है और इसकी निगरानी की जाती है । देश में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों के डिस्ट्रीब्यूटरों के यहां नामांकित वर्तमान एल०पी०जी० उपभोक्ताओं की मांग को पूर्णत: पूरा किया जा रहा है । जब भी कानून और व्यवस्था की समस्याओं, औद्योगिक संबंधों की समस्याओं, बाढ़ आदि के कारण एल पी जी का बैकलाग उत्पन्न हो जाता है, तो तेल कम्पनियां बढ़ाए गए घंटों और रविवारों व अवकाश के दिनों के दौरान एल०पी०जी० भरण संयंत्रों के प्रचालन और वैकल्पिक स्रोतों से आपूर्तियों को बढ़ाने के माध्यम से प्रभावित बाजारों में मांग को पूरा करने के लिए तत्काल कदम उठाते हैं और बैकलाग को समाप्त करती

Allocation of diesel to States

1375. SHRI ISH DUTT YADAV: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) the criteria adopted for allocation of diesel to States;

(b) whether the diesel is being supplied to States as per their demand;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) the action taken by Government to meet their demands in future?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPT. SATISH SHARMA): (a) to (d) Diesel is not an allocated product. It is supplied *in* full as per the demand all over the country.

प्राथमिकता कोटा से इंडियन आयल कारपोरेशन के रसोई गैस (एल०पी०जी०) कनेक्शन

1376. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान इंडियन आयल कारपोरेशन लि० द्वारा प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न प्रकार के कोटों से कितने रसोई गैस कनैक्शन दिए गए हैं ;

(ख) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न प्रकार के कोटों से रसोई गैस (एल.पी.जी.) कनेक्शन देने के संबंध में जारी किए गए पत्रों के मार्ग में गुम हो जाने के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्र रूय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) : (क) वर्ष 1993-94 के दौरान इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड ने विभिन्न कोटा के अन्तर्गत प्राथमिकता आधार पर 94756 इंडेन कनेक्शन जारी किए हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) संसद सदस्यों की सिफारिशों के आधार पर प्राथमिकता वाउचरों के नहीं मिलने के बारे में शिकायतों को दूर करने के लिए एक विशेष प्राथमिकता वाउचर प्रणाली शुरु की गई है । इन विशेष प्राथमिकता वाउचरों को माननीय सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से त्रैमासिक आधार पर वितरित दिया जाता है । मंत्रालय तथा तेल कंपनियों द्वारा जारी किए गए तथा तेल कंपनियों द्वारा पंजीकृत ए डी के अन्तर्गत भेजे गए प्राथमिकता वाउचरों के नहीं मिलने के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं । ऐसे मामलों में रिकार्ड की जांच की जाती है । यदि अपूर्ण पते के कारण पंजीकृत ए डी से भेजा गया प्राथमिकता वाउचर